



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्र 7, 1930

No. 146]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHARDA 7, 1930

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अगस्त, 2008

सं. टीएएमपी/17/2006-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल द्वारा लेबर की आपूर्ति के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/17/2006-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास

—आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2008 के चौदहवें दिन पारित)

यह मामला कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल द्वारा लेबर की आपूर्ति के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सितम्बर, 2002 में टीपीटी के दरमान में संशोधन करते समय, इस प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि यदि पत्तन न्यास द्वारा प्रशासित लेबर पूल के सदस्यों को पत्तन कर्मचारियों के रूप में माना जाता है तो कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए वहां से आपूर्ति के लिए प्रभार्य प्रभार इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसलिए, टीपीटी को सलाह दी गई थी कि वह इस मुद्दे की जांच करे और कार्गो प्रहस्तन कामगार सेवा विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव छह महीनों की समयबद्धि में दायित्व करे।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में टीपीटी ने मौजूदा प्रस्ताव दाखिल किया है। टीपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- (i). तृतीकोरिन पस्तेन नास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) और कार्गो प्रहस्तन कामगार और पूर्वकालिक तृतीकोरिन स्टीवबॉयर्स असोसिएशन (लेबर पूल) के स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाली पांच यूनियनों के बीच औद्योगिक दिवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के अधीन निम्नलिखित ज्ञापन दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 द्वारा निर्मित एक योजना है। यह योजना 1252 कार्गो प्रहस्तन कामगारों और तृतीकोरिन गल्लन में कार्गो प्रहस्तन गतिविधियों में संलग्न स्टाफ का प्रबंधन करता है।
- (ii). निषटारा ज्ञापन के अनुसार, टीपीटीसीएचएलपी कार्गो के प्रहस्तन के लिए विभिन्न नौभरिक एजेंटों की मजदूरी की आपूर्ति करता है।
- (iii). कोयला जेट्टी II, सामान्य कार्गो बर्थ उदाहरणतः वीओसी 1 से 4, अतिरिक्त बर्थ 1 और II, 8वां बर्थ और सैलो जल बर्थ में कार्गो प्रहस्तन प्रचालन के लिए टीपीटीसीएचएलपी से विनियुक्त लेबर के लिए निम्नलिखित प्रभार असूल किए जाते हैं:
 - (क) नियमानुसार, प्रत्येक क्वार्टर डीए धाईदस में परिवर्तनों के अधीन, कर्मचारियों की वास्तविक वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर समय दर मजदूरी।
 - (ख). निर्धारित डेटम के आधार पर पीस-दर मजदूरी।
 - (ग). रात्रि पारियों के दौरान लेबर की वास्तविक तैनाती के अनुसार रात्रि प्रतीक्षा भत्ता।
 - (घ). सांविधिक प्रतिबद्धताओं जैसे चिकित्सा सुविधाएं, वर्दियों का प्रावधान, सुरक्षा सामग्री, पेंशन और उपदान भुगतान, कर्मचारियों के लिए कल्याण व्यय और कार्यालय प्रशासन के लिए प्रशासनिक व्यय भी और अन्य उपरिब्ययों का पूरा करने के लिए प्रति टन आधार पर कार्गो लेवी असूल की जाती है।
- (iv). कार्गो प्रहस्तन गतिविधियों के लिए मजदूरी की आपूर्ति के लिए प्रभार टीपीटी द्वारा लेवी वित्त समिति बैठक में पल्लन उपयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श से निर्धारित किए जाते हैं।
- (v). मौजूदा लेवी ढाँचा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	प्रति मीट्रिक टन (मी0टन)
1.	कोयला और नमक से इतर सभी कार्गो	रु0 41/-
2.	नमक	रु0 15/-
3.	जेट्टी II में कोयला	रु0 850/-
4.	अंतरण शीड और माडामार आदि में सी एंड एफ प्रचालन लेवी	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से
5.	जोन 'ख' के लिए	रु0 10/- प्रति मी0टन

वर्ष 2004-05 से आगे, रियायत तत्संबंधी पिछले वर्ष में प्रहस्तित कार्गो की सर्वार्थत मात्रा पद दी जाती है।

- (vi). मौजूदा लेवी पर इस सेवा से आय और व्यय के अध्ययन पर, यह पाया गया है कि लेवी का वर्तमान स्तर अगले दो वर्षों 2006-07 और 2007-08 के लिए टीपीटीसीएचएलपी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा है। कोयले के लिए मौजूदा लेवी रु0 850 प्रति मी0टन बहुत कम है। मेन पूल कार्गो के संबंध में, उपयोक्ताओं की ओर से इस लेवी को कम करने की मांग है। 4 जनवरी, 2006 को हुई बैठक में पल्लन उपयोक्ताओं के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- (vii). टीपीटी ने तदनुसार मौजूदा लेवी ढाँचे में निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए हैं:
 - कोयले के लिए मौजूदा लेवी रु0 850 प्रति मी0टन से बढ़ाकर रु0 15 प्रति मी0टन करने का प्रस्ताव किया है।
 - प्रमुख पूल कार्गो के लिए लेवी (कोयला जेट्टी II में कोयला और नमक से इतर) में रु0 1 प्रति मी0टन कम करने अर्थात् रु0 41 की मौजूदा लेवी से रु0 40 प्रति मी0टन करने का प्रस्ताव किया गया है जैसाकि उपोक्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है।
 - अन्य कार्गो मदों के लिए लेवी मौजूदा स्तर पर व्यवस्थित की जाती है।
- (viii). इन कामगारों की पेंशन निधि देयता के संबंध में टीपीटी ने निम्नलिखित नियेदन किए हैं

- (क). निपटारा ज्ञापन के कारण से, टीपीटीसीएचएलपी को निपटारा के अधीन शामिल किए गए कर्मचारियों की पेंशन देयता टीपीटी कर्मचारियों के बराबर करनी होती है।
- (ख). टीपीटीसीएचएलपी के अभ्यावेदन और ग्राम मंत्रालय की मंजूरी के आधार पर, टीपीटीसीएचएलपी ने 1 जनवरी, 2003 से पेंशन निधि व्यवस्थित करना शुरू किया था।
- (ग). पेंशन निधि 31 मार्च, 2005 को ₹0 32.39 करोड़ का शेष दर्शाती है।
- (घ). परामर्श जीवनांकक द्वारा किए गए जीवनांककीय मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि देयता 31 मार्च, 2004 तक पेंशन निधि में संचयित किए गए हैं। जीवनांककीय मूल्यांकन को पूरा करने के लिए पेंशन निधि को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए अभी भी ₹0 30.73 करोड़ की शेष राशि की आवश्यकता है।
- (ङ). इस परिप्रेक्ष्य में, पेंशन निधि देयता में कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा लेवी से वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए ₹0 5 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) वसूल करने का प्रस्ताव किया है।
- (ix). टीपीटी ने पेंशन देयता में कमी को पूरा करने के लिए ₹0 5 प्रति मी0टन की प्रस्तावित अतिरिक्त वसूली लागू करते हुए वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमशः ₹0 470.65 लाख और ₹0 486.24 लाख की वसूली का अनुमान लगाया है। टीपीटीसीएचएलपी के मौजूदा लेवी ढाँचे में प्रस्तावित संशोधन वर्ष 2006-07 और 2007-08 में ₹0 146.80 लाख और ₹0 1743.74 लाख की अतिरिक्त आय सृजित करने के लिए अनुमानित की गई है जिसे 31-03-2004 को जीवनांककीय मूल्यांकन के मामले में पेंशन निधि के जल्दी संचयन के लिए इन कामगारों की भविष्य निधि की ओर विपणित करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

3.2. सारबद्ध करने के लिए, कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के साथ-साथ प्रस्तावित लेवी के लिए टीपीटीसीएचएलपी से लेबर की तैनाती के लिए मौजूदा लेवी नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

क्र. सं.	विवरण	मौजूदा लेवी	प्रस्तावित लेवी
1.	मेन पूल कार्गो (कोयला जेट्टी II में कोयला और नमक से इतर)	₹0 41/- प्रति मी0टन	₹0 40/- प्रति मी0टन
2.	कोयला जेट्टी II में कोयला के लिए लेवी	₹0 8.50 प्रति मी0टन	₹0 15/- प्रति मी0टन
3.	नमक के लिए दर	₹0 16/- प्रति मी0टन	₹0 16/- प्रति मी0टन
4.	अंतरण शैंड और भांडागार आदि में सी एंड एफ प्रचालन लेवी	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से
5.	जोन ख	₹0 10/- प्रति मी0टन	₹0 10/- प्रति मी0टन

इसके अलावा, इसने जीवनांककीय मूल्यांकन के आधार पर पेंशन निधि देयता को पूरा करने के लिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए ₹0 5 प्रति मीट्रिक टन वसूल करने का प्रस्ताव किया है।

3.3. टीपीटी ने वर्ष 2006-07 से 2007-08 के लिए लेवी ढाँचे के प्रस्तावित बदलावों के साथ तृतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) के आय और व्यय अनुमान भी भेजे हैं। इसने वर्ष 2003-04, 2004-05 के लिए वास्तविक स्थिति और वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक/अनुमान भी प्रतिवेदित किए हैं।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, टीपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों की प्रतिलिपि टीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। टीपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

5. प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा पर, टीपीटी से कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और टीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	टीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब
(i).	अलग-अलग कार्गो मर्चों के लिए मौजूदा मैनिंग मान और इसे पिछली बार कब संशोधित किया गया था तारीख दर्शाएं।	इसने अलग-अलग कार्गो मर्चों के लिए मौजूदा मैनिंग मान भेजा है। मैनिंग मान पिछली बार 01-01-1984 को संशोधित किया गया था।
(ii).	संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खंड 4.7.3 के अनुसार, पत्तनों के राष्ट्रीय मजदूरी निपटारा के अनुसार समय-समय पर डेटम और पीस-दर योजना की दरों को संशोधित करना होता है; इसके बाद, संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 2.6.2 पत्तन से अपेक्षा करता है कि वह प्रौद्योगिकी बदलावों के मद्देनजर मैनिंग मान की नियमित रूप से समीक्षा करें। इस दिशा में पत्तन द्वारा शुरू की गई कार्यवाई सुचित करें।	भारतीय पत्तन असोसिएशन और फेडरेशन ऑफ पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन के बीच मजदूरी संशोधन निपटारा के अनुसार गठित राष्ट्रीय अधिकरण डेटम और मैनिंग मान के संशोधन के मुद्दे पर कार्यवाही कर रहा है। चूंकि राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय डब्ल्यूआरआर निपटार के अनुसार बाध्य है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई तदर्थ निर्णय समय-पूर्व माना गया है।
(iii).	पिछले दो वर्षों के लिए कार्गो प्रहस्तन कामगारों के नियोजन के औसत दिन दर्शाएं।	पिछले दो वर्षों 2004-05 और 2005-06 के लिए कामगारों के नियोजन के औसत दिन भेजे गए हैं। भेजे गए अंकड़ों के अनुसार, लेबर के नियोजन के औसत दिन एक माह में 12 से 15 दिन हैं।
(iv).	औसत आउटपुट के अनुसार पिछले दो वर्षों के लिए कार्गो प्रहस्तन कामगारों की प्रति हुक प्रति घण्टी घटक-वार उत्पादकता दर्शाएं।	पिछले दो वर्षों 2004-05 और 2005-06 के लिए घटक-वार औसत आउटपुट प्रति हुक प्रति घण्टी भेजे गए हैं।
(v).	प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 4.7.2 अनुशरण करता है कि नौमरण सेवाएं प्रदान करने के लिए पत्तन प्रशुल्क संबंध उत्पादकता निर्धारित करें। इसलिए, टीपीटी का उत्पादकता स्तर में वृद्धि के साथ स्लाइडिंग दरें निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। ऐसी प्रशुल्क व्यवस्था मुरुगांव पत्तन न्यास में प्रचलन में है।	मुरुगांव पत्तन न्यास में उत्पादकता से संबंध स्लाइडिंग दरों का उपयुक्त निर्णय, यदि आने वाले समय में कार्यान्वयन के लिए लागू होगा, के लिए विस्तारण किया जाएगा।
(vi).	स्पष्ट करें कि क्या मौजूदा लेवी टीपीटी के पिछले सामान्य संशोधन आदेश से पहले भारत सरकार द्वारा पहले अनुमोदित की गई थी।	तृतीकोरिन नौमरिक असोसिएशन (लेबर पूल) के पूर्ववर्ती प्रशासन ने वेतन/मजदूरी और अन्य लाभों के अनुसार राबड़ी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लेवी की मात्रा निर्धारित करने हेतु नौमरिकों की एक लेबी समिति का गठन किया था। 01 जनवरी, 2000 से टीपीटीसीएचएलपी के गठन पर, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली प्रबंध समिति टीपीटीसीएचएलपी के मामलों के प्रबंधन के लिए गठित की गई थी। पत्तन अधिकारियों और उपयोक्ताओं को शामिल करते हुए एक लेवी वित्त समिति का गठन भी किया गया था। पेशन देयता सहित वेतनों और अन्य लाभों संबंधी लेबर पूल की प्रतिबद्धता लेवी वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई है और चर्चा के पश्चात्, लेवी में बढ़ोतरी/कटौती सहमति के आधार पर परिगणित की गई है। पूर्वकाल में सरकारी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था इसलिए वर्तमान में टीपीटी द्वारा प्रभावी लेवी की राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
(vii).	टीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन प्रचालकों के लिए टीपीटीसीएचएलपी की तैनाती के लिए मौजूदा प्रति टन लेवी पर पहुंचने का आधार स्पष्ट करें। इस संबंध में प्रत्येक कार्गो मर्चों के लिए विस्तृत परिकल्पना भी भेजें।	तृतीकोरिन रटीवडोस असोसिएशन के पूर्ववर्ती प्रशासन ने कुछ पत्तनों में यथा अंगीकृत प्रतिशत आधार की बजाय प्रति टन आधार पर लेवी वसूल करने की पद्धति का अनुसरण किया है। प्रति टन लेवी पर पहुंचने का आधार नीचे स्पष्ट किया है: (क). सभी ध्वज सब्सिडी प्रतिबद्धता की मात्रा का निर्धारण किया गया है। (ख). प्रहस्तित कार्गो में पूल कार्गो कोयला जेट्टी II में प्रहस्तित कार्गो और नमक में बांटा गया है। (ग). प्रति टन दर विभिन्न कार्गो वर्गीकरण के लिए औसत हुक पारी के आधार पर और अनुमानित टनभार द्वारा प्रमाणित व्यय को बांटते हुए सभी ध्वज (नौमरिकों से वसूल की गई मजदूरी और

		पीस-दर से इतर) के प्रमाणन द्वारा निर्धारित की गई है। यह बताना उल्लेखनीय है कि कुछ प्रति-सहायिकी नमक जैसे कार्गो के लिए आवश्यक है। कॉपर कंसट्रेट, रॉक फॉस्फेट, औद्योगिक कोयला जैसा बल्क कार्गो कम मात्रा के साथ-साथ कम मात्रा कार्गो से प्रति सहायिकी करता है। चूंकि कई प्रकार का कार्गो टीपीटी में प्रहस्तित किया जाता है और उसी कार्गो के प्रहस्तन के लिए एजेंटों द्वारा विभिन्न पद्धतियां अंगीकृत की जाती हैं, प्रत्येक कार्गो के लिए गणना पत्रक उपलब्ध नहीं है।
(viii).	पेंशन निधि की ओर विपश्चित किए जाने के लिए प्रस्तावित राशि घटाए बिना मौजूदा लेवी पर टीपीटीसीएचएलपी के लिए आय और व्यय विवरण भेजें।	पेंशन निधि लेवी में अंशदानों को नज़रअंदाज करते हुए आय और व्यय विवरण अलग-से भेजा गया है।
(ix).	अचल परिसंपत्तियों पर पहुंचने का आधार और यह सेवा ऑफर करने के लिए कार्यगत पूंजी की प्रासंगिकता इस अनुमानन के लिए विस्तृत आधार के साथ स्पष्ट करें।	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मूल्यहास के लिए उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात् लिखा गया मूल्य टीपीटीसीएचएलपी की अचल परिसंपत्तियों पर पहुंचने के लिए आधार है। कार्यगत पूंजी पेंशन संबंधी मासिक प्रतिबद्धता सहित औसत वित्तीय प्रतिबद्धता के आधार पर निर्धारित की गई है। डब्ल्यूआरसी निपटान के अनुसार टीपीटीसीएचएलपी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन/लाभों के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है।
(x).	कार्गो प्रहस्तन कामगारों के लिए पेंशन के जीवनांककीय मूल्यांकन का विस्तृत परिकलन भेजें। इस संबंध में जीवनांककीय की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजें।	31 मार्च, 2004 को पेंशन देयता के जीवनांककीय प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। इसने बाद में पेंशन निधि लेवी का विस्तृत परिकलन भेजा है।
(xi).	पिछले दो वर्षों के लिए टीपीटीसीएचएलपी के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतिलिपि भेजें। 31 जनवरी, 2006 तक वर्ष 2005-06 के लिए उगाहियां बताएं।	इसने पिछले तीन वर्षों 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए टीपीटीसीएचएलपी के लेखा परीक्षित लेखों की प्रत्येक प्रतिलिपि भेजी है।
(xii).	पेंशन निधि देयता की वसूली के प्रयोजन के लिए केवल कोयला प्रहस्तन के लिए मौजूदा लेवी में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य दें।	यह कहना सही नहीं है कि पेंशन निधि के प्रयोजन के लिए केवल संवर्धित कोयला लेवी का इस्तेमाल किया गया। यह बताया गया है कि सभी कार्गो मर्दे पेंशन निधि देयता को योगदान प्रदान करती हैं। पेंशन निधि देयता लेबल पूल की प्रतिबद्धता है और इसे जीवनांककीय मूल्यांकन के अनुसार संचयित किया जाना चाहिए। नमक से इतर मेन पूल की अन्य कार्गो मर्दों की लागत पर सभी के साथ कोयला पर छूट दी गई है। अनुमानित व्यय स्तर पर गैर पारी आउटपुट के आधार पर निर्धारित प्रति टन लागत दर्शाते हुए गणना का विवरण संलग्न किया गया है। इस गणना के आधार पर, कोयला के लिए लेवी को ₹0 17.64 प्रति मी0ट0 की प्रति टन लागत के विपरीत ₹0 15 प्रति मी0ट0 करने का प्रस्ताव किया गया है।
(xiii).	पेंशन निधि देयता को पूरा करने के लिए एक पृथक प्रति टन लेवी रोकी जानी चाहिए जब जीवनांककीय मूल्यांकन पर आधारित पेंशन अंशदान वसूल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए अलग से व्यवस्थित किए गए लेखा शीर्ष की नियमित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।	इसने पुष्टि की है कि ₹0 5/- प्रति मी0ट0, पेंशन निधि देयता को पूरा करने के लिए पेंशन निधि लेवी के रूप में चिह्नित किया गया है और जीवनांककीय मूल्यांकन के अनुसार देयता जब कभी पूर्ण हो जाएगी इसे रोक दिया जाएगा। इसने दोहराया है कि प्रस्तावित पेंशन निधि लेवी एक बार का करार है और इसे अलग से व्यवस्थित किया जाना जारी रखा जाएगा। लेखों का पृथक शीर्ष बनाए रखने का सही तथ्य स्वतः अनुवीक्षण कार्यविधि के रूप में कार्य करता है।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई तृतीकोरिन पत्तन न्यास में 13 जुलाई, 2007 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में टीपीटी और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोसिएशनों ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे। तृतीकोरिन कस्टम हाऊस एजेंट्स असोसिएशन (टीसीएचए) ने पहले कही गई बातों को दोहराते हुए लिखित निवेदन दायरित किए हैं। उसके अलावा, इसने मेन पूल कार्गो पर लेवी

को ₹0 41/- से घटाकर ₹0 31/- प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) किए जाने के लिए प्रशंसा की है और इसे आगे और कम ₹0 25/- प्रति मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है यदि कम नहीं किया जाता है।

7. सचुक्त चुनवाई में यथा सहमत, टीपीआई को पिछले 3 वर्षों के लिए वास्तविक स्थिति देते हुए संशोधित लागत विवरण वर्ष 2009-10 तक अनुमानों के साथ संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई थी ताकि वैधता सामान्य संशोधन मामले के साथ को-टर्मिनर किया जा सके।

8.1. चुनौतीकरण पलान ने तदनुसार सितम्बर, 2007 में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। इसने वर्ष 2006-07 तक वास्तविक आंकड़े अधुनातन करते हुए संशोधित विवरण भी प्रस्तुत किए थे और वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए अनुमानों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए टीपीटी द्वारा दाखिल संशोधित विवरण का सार वर्ष 2004-05 से 2006-07 के वास्तविक आंकड़ों के साथ नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक			अनुमान			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए औसत
1.	प्रचालन व्यय	2662.89	2689.27	2770.00	2919.58	3077.24	3243.41	3080.07
2.	एफ एड एम व्यय	1003.66	755.85	729.34	768.25	809.74	855.46	810.48
3.	वैतन/मजदूरी संशोधन 25 प्रतिशत				446.64	669.97	673.31	596.64
4.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	15.22	16.48	16.96	19.22	19.22	19.22	19.22
5.	कुल व्यय	3681.77	3461.60	3516.30	4153.69	4556.17	4789.40	4506.41
6.	घटाए वसूल की गई मजदूरी	1252.35	1387.10	1539.33	1630.06	1692.03	1753.08	1691.72
7.	वसूल किया जाने वाला शेष व्यय	2429.42	2074.50	1976.97	2523.63	2864.14	3036.32	2814.69

8.2. औसत हुक पारियों के आधार पर संशोधित प्रस्तावित लेवी पर पहुंचने के लिए टीपीटी द्वारा भेजी गई परिगणना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	औसत हुक पारियाँ	वसूल किया जाने वाला व्यय (रुपये लाखों में)	औसत प्रहस्तित टनमार (लाख टनों में)	दर प्रति टन (रुपयों में)	पेंशन निधि लेवी (₹0 प्रति टन)
1.	मेन पूल -- अन्य	17037	2363.09	77.00	31	4.30
2.	कोयला जेट्टी II में टी/कोयला	2855	395.99	12.00	12	4.30
3.	नमक	401	55.82	1.00	56	4.30
	कुल	20293	2814.70	110.00		

8.3. तदनुसार, टीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित लेवी डॉचा के साथ-साथ इसका प्रारंभिक प्रस्ताव निम्नवत है:

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित लेवी	संशोधित प्रस्ताव में प्रस्तावित लेवी
1.	मेन पूल कार्गो के लिए लेवी (कोयला जेट्टी II में कोयला और नमक से इतर)	₹0 40/- प्रति मीट्रिक टन	₹0 31/- प्रति मीट्रिक टन
2.	कोयला जेट्टी II में कोयला के लिए लेवी	₹0 15/- प्रति मीट्रिक टन	₹0 12/- प्रति मीट्रिक टन
3.	नमक के लिए दर	₹0 18/- प्रति मीट्रिक टन	₹0 56/- प्रति मीट्रिक टन
4.	अंतरण शीड और शांदाशर आदि, में सी एड एफ प्रचालन लेवी	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से
5.	जोन 'ख' के लिए	₹0 10/- प्रति मीट्रिक टन	₹0 10/- प्रति मीट्रिक टन

पेंशन निधि देयता में कमी को पूरा करने के लिए, प्रारंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित ₹0 5/- प्रति मीट्रिक टन के विपरीत, जीवनांककीय मूल्यांकन के आधार पर, उपर्युक्त क्रम सं. 1, 2 और 3 में उल्लिखित मदों के लिए ₹0 4.30 प्रति मीट्रिक टन की पेंशन निधि लेवी अगले पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित की गई है।

8.4. टीपीटी द्वारा भेजा गया पेंशन निधि लेवी का विस्तृत परिकलन नीचे दिया गया है:

		रुपये लाखों में
1.	31-03-2007 को जीवनांकिकीय मूल्यांकन	7800.00
2.	2006-07 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन निधि बकाया	4600.00
3.	जोड़े: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से प्राप्त होने वाली संभावित बकाया राशि	846.34
4.	31 मार्च, 2007 को पेंशन निधि में उपलब्ध कुल निधि	5446.34
5.	जीवनांकिकीय मूल्यांकन (1-4) को पूरा करने के लिए पेंशन निधि में कमी	2353.66
6.	5 वर्षों में वसूल की जाने वाली पेंशन निधि में कमी	470.73
7.	पेंशन निधि लेवी (6/औसत संभावित टनभार अर्थात् 110 लाख टन प्रति वर्ष)	4.30

इसने तदनुसार मेन पूल कार्गो, कोयला जेट्टी II पर कोयला और नमक मामले में रु० 4.30 प्रति मी०टन की पेंशन निधि लेवी को अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित रु० 5/- प्रति मी०टन की अपेक्षा कम करने का प्रस्ताव किया है।

9. संशोधित प्रस्ताव में देखे गए कुछ अंतरों के मद्देनजर, टीपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और टीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	टीपीटी से प्राप्त जवाब
(i).	वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतिलिपि।	इसने वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतिलिपि भेजी है।
(ii).	टीपीटीसीएचएलपी द्वारा तैनात लेबर पूल द्वारा प्रहस्तित किए जाने वाले अनुमानित यातायात का आधार, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए आय और व्यय अनुमान भेजें।	वर्ष 2007-08 के लिए अनुमानित यातायात जुलाई, 2007 में प्रहस्तित यातायात के संदर्भ में अनुपाततः परिगणित किया गया है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए, यातायात वृद्धि 5 प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष पर सुविचारित की गई है। पिछले वर्ष की वास्तविकताओं/अनुमानों के संदर्भ में 5.4 प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष पर विचार करते हुए व्यय अनुमानित किए गए हैं।
(iii).	(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए पेंशन निधि में अंशदान के साथ-साथ एफएमई में पेंशन भुगतानों/परिवर्तन दोनों के शामिल होने के कारण। यह उल्लेखनीय है कि पेंशन निधि से आहरण नहीं किए जाने की सीमा तक पेंशन भुगतानों और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देयता के संबंध में प्रासंगिक वर्षों के लिए पेंशन निधि में किया गया अंशदान प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में स्वीकार्य होगा।	पेंशन निधि में अंशदान और सामान्य लेखा से किए गए पेंशन भुगतानों के संबंध में, पेंशन निधि में अंशदान मूल बेटन और डीए पर 15 प्रतिशत पर परिगणित वर्ष 2007-08, 2008-09 के प्रत्येक वर्ष की देयता का प्रतिनिधित्व करता है और पेंशन भुगतान राजस्व व्यय से नहीं किए गए हैं। इसलिए यह सही है। पेंशन भुगतान/पेंशन का परिवर्तन मौजूदा पेंशनर पर किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, पेंशन निधि में अंशदान प्रत्येक वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले पेंशन निधि संबंधी वार्षिक देयता का प्रतिनिधित्व करता है।
	(ख) पुष्टि करें कि मजदूरी में बकाया, वीआरएस क्षतिपूर्ति जैसे एक-समय वाले व्ययों को संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खंड 2.5.2 के अनुसार एफएमई से अलग रखे गए हैं।	इसकी पुष्टि की गई है कि मजदूरी में बकाया, वीआरएस क्षतिपूर्तियाँ जैसे एक-बार के व्यय एफएमई व्यय में शामिल नहीं किए गए हैं।
(iv).	अपने संशोधित प्रस्ताव में सुविचारित आंकड़ों के संदर्भ में वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए नियोजित पूंजी और आरओसीई का विस्तृत परिकलन भेजें। नियोजित पूंजी परिकलन करते समय, कार्यगत पूंजी संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमानित की जा सकती है।	इसने नियोजित पूंजी का विस्तृत परिकलन भेजा है जिसमें अचल परिसंपत्तियाँ और कार्यगत पूंजी शामिल है।
(v).	(क) संशोधित प्रस्ताव में 30 जून, 2007 को रु० 78 करोड़ पर अनुमानित कार्गो प्रहस्तन कामगारों के लिए पेंशन निधि के जीवनांकिकीय मूल्यांकन का विस्तृत परिकलन भेजें। इस संबंध में जीवनांकिकीय की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजें।	इसने निर्दिष्ट किया है कि पेंशन निधि का जीवनांकिकीय मूल्यांकन 31 मार्च, 2007 को रु० 78.34 करोड़ होगा।

<p>(ख). पेंशन लेवी के परिकलन में सुविचारित (आरपीएफसी से) ₹0 4600 लाख और ₹0 846.34 लाख का पेंशन शेष वर्ष 2006-07 के लिए टीपीटीसीएचएलपी के वार्षिक लेखों में नहीं पाया गया है।</p> <p>इस अनुमान को कुछ दस्तावेजी समर्थन के साथ जहां से यह लिया गया है, प्रमाणित करें।</p>	<p>₹0 4600 लाख का पेंशन निधि शेष निम्नलिखित संघनों पर आधारित है:</p> <p>(रूपये लाखों में)</p> <table border="1"> <tr> <td>1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) से प्राप्त कर्मचारी अंशदान</td> <td>1,893.83</td> </tr> <tr> <td>2. वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिए पेंशन निधि लेवी</td> <td>1,969.95</td> </tr> <tr> <td>3. सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और सार्वजनिक जमा राशियों से निवेश पर अर्जित व्यय</td> <td>736.22</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>4,600.00</td> </tr> </table>	1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) से प्राप्त कर्मचारी अंशदान	1,893.83	2. वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिए पेंशन निधि लेवी	1,969.95	3. सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और सार्वजनिक जमा राशियों से निवेश पर अर्जित व्यय	736.22	कुल	4,600.00
1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) से प्राप्त कर्मचारी अंशदान	1,893.83								
2. वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिए पेंशन निधि लेवी	1,969.95								
3. सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और सार्वजनिक जमा राशियों से निवेश पर अर्जित व्यय	736.22								
कुल	4,600.00								
<p>(ग). तीन वर्षों 2007-08 से 2009-10 के दौरान पेंशन निधि शेष पर संभावित प्रोद्भूत व्यय भी पेंशन निधि लेवी निर्धारित करने के लिए सुविचारित किया जाए।</p>	<p>₹0 846.34 लाख (आरपीएफसी से देय) के संघ में, यह राशि आरपीएफसी, तिरुनेलवेली से ₹0 575.03 लाख 31-12-2002 तक व्यय के साथ, जिसके परवर्त, टीपीटीसीएचएलपी ने प्रबंधन किया था, प्राप्त होने वाले आहरण लाभों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूर्वकालिक ह्यूमकोरिन स्टीवडोर्स असोसिएशन द्वारा 31-12-1999 तक दिए गए निधोक्ता अंशदान के स्थान पर है।</p>								
<p>(vi). टीपीटी ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में जोकि उपयोक्ताओं को परिचालित किया गया था के साथ ही 13 जुलाई 2007 को हुई सशुक्त मुन्वाई में नमक के मामले में ₹0 18/- प्रति मीट्रिक टन की मौजूदा लेवी जारी रखने का प्रस्ताव किया था। संशोधन प्रस्ताव में नमक पर लेवी को ₹0 18/- प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹0 56/- प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव रखने के कारण और आधार को तर्कसंगत सिद्ध किए जाने की जरूरत है क्योंकि ऐसी संशोधन इसके प्रारंभिक प्रस्ताव जोकि उपयोक्ताओं को परिचालित किया गया था का हिस्सा नहीं था।</p>	<p>₹0 18/- प्रति टन की प्रस्तावित दर नमक की प्रचलित दर प्रदर्शित करती है। ₹0 56/- प्रति मीट्रिक टन की दर इसके हुक पारी टनभार के सद्वर्ग से नमक से वसूल की जाने वाली लेवी की वास्तविक दर निर्दिष्ट करने के लिए है। तथापि, ₹0 18/- प्रति मीट्रिक टन नमक के लिए लेवी की वास्तविक दर होगी।</p>								
<p>(vii). (क). टीपीटी ने अपने पत्र दिनांक टीपीटीसीएचएलपी/एसओआर/आरईवी/2006-डी दिनांक 21 जून, 2006 में स्पष्ट किया था कि प्रारंभिक प्रस्ताव में अंतरण शीड और भांडागार आदि पर सी एंड एफ प्रचालन के लिए समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की प्रस्तावित दर सही नहीं थी। टीपीटी ने पुष्टि की थी कि प्रभावी मौजूदा लेवी के अनुसार, कार्गो जिसमें कंटेनर भरण/खाली करना प्रचालन मजदूरी की समय दर और अंतरण शीड, भांडागार और जोन ख में कार्गो प्रहरण के लिए लेवी ₹0 10/- प्रति मीट्रिक टन है। तथापि, टीपीटी द्वारा दायित्व संशोधित प्रस्ताव उक्त संशोधन को नहीं दर्शाता है।</p>	<p>मजदूरी की समय दर का 200 प्रतिशत कंटेनर भरण और खाली करना प्रचालनों के लिए है। सी एंड एफ प्रचालनों, अंतरण शीड, भांडागार और जोन ख जैसे अन्वयों के लिए, यह पुष्टि की गई है कि ₹0 10/- प्रति मीट्रिक टन की दर अच्छी है। इसे प्राधिकरण के आदेश में उपयुक्तता शामिल किया जा सकता है।</p>								
<p>(ख). अंतरण शीड और भांडागार में सी एंड एफ प्रचालनों के लिए ₹0 10/- प्रति मीट्रिक टन और अंतरण शीड तथा भांडागार में भरण और खाली करना प्रचालनों और सी एंड एफ प्रचालनों वाले कार्गो के लिए समय दर मजदूरी का 200 प्रतिशत लेवी पर पहुंचने के लिए परिकल्पनाएं भर्त्ता।</p>	<p>सी एंड एफ प्रचालनों के उक्त प्रचालन बहुत मीजर हैं। मजदूरी के समय दर का 200 प्रतिशत के लिए गणनाएं पहले ही भेजी जा चुकी हैं। अंतरण शीड और जोन ख में सी एंड एफ प्रचालन के लिए ₹0 10/- मीट्रिक टन के संबंध में यह परम्परागत दर है और मीजर प्रचालन के कारण है। इस संबंध में वसूल की गई राशि पिछले दो वर्षों के लिए लगभग शून्य है।</p>								
<p>(viii). यद्यपि यह लेवी अन्य फीट उदाहरणतः अंतरण शीड और भांडागार में सी एंड एफ प्रचालन और भरण तथा खाली करना प्रचालनों वाले कार्गो से वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है परंतु टीपीटीसीएचएलपी</p>	<p>टीपीटी द्वारा भेजी गई गणना से, यह पाया गया कि टीपीटीसीएचएलपी का अपूर्णत व्यय में पूल कार्गो, कोयला जेट्टी 11 में प्रहसित कोयला और नमक से वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अंतरण शीड, भांडागार में सी एंड एफ के</p>								

संबंधी व्यय इन कार्गो मर्चों/गतिविधियों में प्रभावित किया जाना नहीं पाया गया है। आय अनुमान भी इन मर्चों से आय नहीं दर्शाता है। उपर्युक्त कमी के आलोक में, टीपीटी को यह स्थिति दर्शाने के लिए विवरण को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।	अन्य प्रचालन बहुत मौजूर है और वसूली केवल लगभग ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष है।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

10. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों के अलग से भेजा जाएगा। ये खोरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

11. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:

(i). दिसम्बर, 1999 में हुए औद्योगिक निपटारे के परिणामस्वरूप, तूतीकोरिन स्टीमडोर्स असोसिएशन (लेबर पूल) के कामगारों और स्टाफ को पृथक योजना के अधीन लाया गया था जिसे तूतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो प्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) के नाम से जाना जाता है।

टीपीटीसीएचएलपी से कार्गो प्रहस्तन कामगारों की आपूर्ति के लिए लेबी टीपीटी द्वारा लेबी वित्त समिति बैठक में पत्तन उपयोगिताओं के साथ विचार-विमर्श से निर्धारित किए जाने के बारे में बताया गया है।

टीपीटीसीएचएलपी का प्रशासनिक कार्य टीपीटी द्वारा किया जाता है यद्यपि एक भिन्न नाम के अधीन। पूल से कार्गो प्रहस्तन कामगारों की आपूर्ति के लिए दरें इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जानी अपेक्षित है क्योंकि यह धारा 48 के अधीन सूचीबद्ध सेवा से संबंधित है। वर्ष 2002 में पत्तन के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन के समय टीपीटी को इस स्थिति से अवगत करवाया गया था। दी गई सलाह के आधार पर कार्य करने में टीपीटी को लगभग चार वर्षों का समय लगा।

इस संकट पर, यह प्राधिकरण समिति द्वारा निर्धारित दर, महापत्तन न्यास अधिनियम के उपबंधों के अधीन इसका स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना और इस मुद्दे पर उपयोक्ताओं में से किसी ने भी विरोध नहीं किया है, के आधार पर प्रसार्य प्रभावों की प्रक्रियात्मक प्रभुत्व पर नहीं जाना चाहेंगे।

(ii). टीपीटी ने निर्दिष्ट किया है कि अलग-अलग घटकों के लिए मौजूदा मैनिंग मानों को वर्ष 1984 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। मैनिंग मानों, डैटम और पीस दर प्रोत्साहनों में संशोधन के लिए वर्ष 1999 के निपटारा ज्ञापन में प्रावधान है। कुछ उपयोक्ताओं ने बताया है कि मैनिंग पैटर्न, डैटम स्तर की इस पत्तन द्वारा जाँच किए जाने और युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है और इस प्राधिकरण से भी अनुरोध किया है कि लेबी में संशोधन करने से पहले इस मुद्दे को देखा जाए।

प्रशुल्क दिशा-निर्देश पत्तन से अपेक्षा करते हैं कि प्रौद्योगिक बदलावों के मद्देनजर मैनिंग मान की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। पत्तन से यह अपेक्षा भी की जाती है कि राष्ट्रीय मजदूरी निपटारों के अनुसार समय-समय पर डैटम और पीस-दर योजना की दरों में संशोधन किया जाए।

तथापि, टीपीटी ने माना है कि भारतीय पत्तन असोसिएशन और फेडरेशन ऑफ पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन के बीच मजदूरी संशोधन निपटान के अनुसार गठित राष्ट्रीय अधिकरण ने डैटम/मैनिंग मान के संशोधन के मुद्दे को लिया है। चूंकि राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय मजदूरी संशोधन समिति निपटार के अनुसार बाध्यकारी है, इसलिए टीपीटी महसूस करता है कि इस मुद्दे पर कोई तदर्थ निर्णय समय-पूर्व माना जाएगा।

यह स्वीकार किया गया है कि अंगीकृत मैनिंग मानों और डैटम के आधार पर मजदूरी लागत से निश्चित रूप से प्रशुल्क बाध्यता पड़ेगी। यह स्वीकार करना होगा कि मैनिंग मानों और डैटम का निर्धारण एक पत्तन प्रबंधन कार्य है। चूंकि महापत्तनों के डैटम/मैनिंग मान में संशोधन राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा विचारधीन बताया गया है, इसलिए लेबी टीपीटी द्वारा प्रस्ताव में प्रतिवेदित मौजूदा मैनिंग मान/डैटम के आधार पर निर्धारित की गई है।

इस प्रशुल्क मामले में इस स्थिति के बावजूद, टीपीटी को सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय स्तर मजदूरी करार में शामिल उपबंधों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए डैटम को संशोधित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए।

(iii). टीपीटी के मूल प्रस्ताव के प्रतिपाद में, बहुत से उपयोक्ताओं ने मेन पूल कार्गो के मामले में लेबी में और अधिक कटौती करने की माँग की थी। टीएनईवी ने कोयले के लिए प्रस्तावित दर को स्पष्ट किया जाना पाया था और पत्तन से दर को कम करने का अनुरोध किया था।

टीपीटी ने उपयोक्ताओं की माँग को स्वीकार किया और मेन पूल कार्गो के लिए लेबी कम करने हेतु अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित ₹ 40/- को ₹ 35/- प्रति मीटन और कोयला प्रहस्तन के लिए ₹ 10/- प्रति मीटन करने के लिए संयुक्त सुनवाई में सहमत हो गए थे। तथापि, लागत स्थिति पर विश्वास करते हुए टीपीटी द्वारा बाद में दाखिल किए गए संशोधित प्रस्ताव में संयुक्त सुनवाई में सहमत स्थिति से कुछ भिन्नताएँ थीं।

- (iv). टीपीटी द्वारा दाखिल किए गए टीपीटीसीएचएलपी के लागत विवरण की प्रस्तुतित दसों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए जांच की गई है।

टीपीटी ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए टीपीटीसीएचएलपी गतिविधि का वास्तविक आय और व्यय तथा अगले तीन वर्षों 2007-08 से 2009-10 के लिए अनुमान भेजे हैं। वर्ष 2007-08 पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, केवल वर्ष 2008-09 और 2009-10 के अनुमान ही इस प्रशुल्क निर्धारण कार्यवाही में प्रासंगिक होंगे। परिणामस्वरूप, अब अनुमोदित की जाने वाली संशोधित लेवी की वैधता इसके कार्यान्वयन की तारीख से लगभग डेढ़ वर्ष की पूर्वकालिक वैधता अवधि होगी।

टीपीटीसीएचएलपी के मेन पूल द्वारा प्रहस्तित किए जाने के लिए संभावित कार्यों मात्रा तत्संबंधी पिछले वर्ष की वास्तविकताओं/अनुमानों से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक अधिक अनुमानित की गई है। टीपीटीसीएचएलपी द्वारा प्रहस्तित किए जाने वाले कोयला यन्त्रायात की मात्रा विचाराधीन तीन वर्षों के लिए लगभग वर्ष 2006-07 के स्तर पर अनुमानित की गई है।

सामान्य संशोधन प्रस्तुत में टीपीटी द्वारा अनुमानित यातायात वृद्धि इस भावना विशेष के लिए पूर्णतः प्रासंगिक नहीं हो सकती क्योंकि सभी कार्यों टीपीटीसीएचएलपी की सेवाएं प्राप्त नहीं करेंगे। लेवी के निर्धारण हेतु इस मामले में टीपीटी द्वारा अनुमानित यातायात पर विश्वास किया गया है।

तथापि, यदि गलत अनुमानन के कारण टीपीटी को अनावश्यक लाभ होना पाया जाएगा तो प्रशुल्क की अगली समीक्षा के समय प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशुल्क में समायोजन किया जाएगा।

- (क). वर्ष 2007-08 के लिए प्रचालन व्यय वर्ष 2006-07 में प्रतिवर्षित वास्तविक आंकड़ों से 5.4 प्रतिशत तक ज्यादा अनुमानित किया गया है। अनुवर्ती दो वर्षों 2008-09 और 2009-10 के लिए व्यय 5.4 प्रतिशत का समान वृद्धि कारक लागू करते हुए अनुमानित किए गए हैं।

(ख). व्यय और विविध व्यय का अनुमानन में पेंशन/उपदान भुगतानों के साथ-साथ विचाराधीन वर्षों के लिए पेंशन निधि और उपदान निधि में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि टीपीटीसीएचएलपी कामगारों के लिए पेंशन भुगतान राजस्व लेखा और मूल तथा डीए के 15 प्रतिशत की सीमा तक पेंशन निधि में किए गए वार्षिक अंशदान संबंधी प्रावधान से किया जाता है। मौजूदा पेंशनरों का पेंशन भुगतान पेंशन निधि से किया जाता है; मौजूदा पेंशनरों का पेंशन भुगतान पेंशन निधि से पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, केवल लेवी के निर्धारण हेतु पेंशन निधि और उपदान निधि में किए जाने के लिए प्रस्तावित अंशदान टीपीटी द्वारा यथा अनुमानित प्रस्तावित किया गया है।

(ग). वर्ष 2007-08 के लिए कुल वेतन और मजदूरी रु० 1786.57 लाख अनुमानित की गई है। टीपीटी ने वर्ष 2007-08 के लिए कुल मजदूरी लागत के 25 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान किया है। यह स्वीकार करते हुए कि यह मंच केवल एक प्रावधान है, विशेषाज्ञापन पत्तन न्यास, न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास जैसे अन्य महापत्रानों के साथ-साथ टीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव जिसपर अलग से कार्यवाही की जा रही है, के लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2007-08 के लिए अनुमानित मजदूरी लागत के 15 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार करने के लिए यह पर्याप्त पाया गया है।

टीपीटी ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के प्रत्येक वर्ष के लिए मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की है। पत्तन ने इन दो वर्षों के दौरान लेबर बल की संख्या में कोई वृद्धि अनुमानित नहीं की है। वास्तव में पत्तन ने लेबर बल को कम करने के लिए पिछले कुछ समय के दौरान किए गए प्रयासों पर जोर दिया है। इसलिए, अनुमान वार्षिक वृद्धि स्तर जोकि 4.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर सुविचारित किया गया है, से अधिक अनुमानित मजदूरी लागत पर विचार करने के लिए कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान उस सीमा तक उपयुक्ततः संशोधित किए गए हैं।

- (घ). टीपीटी ने वर्ष 2004-05 के लिए कार्यगत पूंजी परिकलित की है और वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए कार्यगत पूंजी के अनुमानन हेतु अनुवर्ती वर्षों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू की है। कार्यगत पूंजी का परिकलन प्रशुल्क दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है। प्रशुल्क दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के आधार पर वर्ष 2006-07 के लिए कार्यगत पूंजी नकारात्मक आंकड़े में परिणमित की गई है। इसलिए, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए कार्यगत पूंजी का अनुमान शून्य रूप में लिया गया है।

टीपीटी ने पुष्टि की है कि मूल्यह्रास प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्पनी अधिनियम के अनुसार, जोकि स्वीकार्य है, परिकलित किया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित अचल परिसंपत्तियों का मूल्य और वह नियोजित पूंजी के परिकलन में शामिल किया गया है, मुख्यतः मूल्यह्रास के परिकलन की भिन्न-भिन्न पद्धति के कारण भिन्न है।

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए लागत विवरण में टीपीटी द्वारा भेजे गए निवल अचल परिसंपत्तियों के मूल्यों पर इस विश्लेषण में विश्वास किया गया है। टीपीटी ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए नियोजित पूंजी का परिकलन नहीं भेजा था। इस सूचना के अभाव में और यह स्वीकार करते हुए भी कि पत्तन में तीन वर्षों के दौरान परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड में कोई संवर्धन प्रस्तावित नहीं किया है, अनुवर्ती वर्षों 2008-09 और 2009-10 के लिए निवल अचल परिसंपत्तियां पिछले वर्ष के निवल प्रखंड के अनुमानों से मूल्यहास राशि को कम करते हुए विपश्चित किया गया है।

- (vii). (क). टीपीटीसीएचएलपी का औसत कुल व्यय और उपर्युक्त संशोधन करने के पश्चात नियोजित पूंजी पर प्रतिवर्ष वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए ₹ 3822.89 लाख परिगणित किया जाना चाहिए। इसमें से, मजदूरी की ₹ 1722.56 लाख की औसत प्रासंगिक वर्षों के लिए टीपीटी द्वारा वसूल किए जाने वाली अनुमानित की गई है। ₹ 2100.13 लाख का शेष व्यय प्रस्तावित लेवी के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।

अनुमानित व्यय औसत हुक पारियों के आधार पर कार्गो मर्दों में बांटा गया है और प्रति टन कार्गो लेवी प्रहस्तित किए जाने के लिए संभावित कार्गो की मात्रा परिकलित की गई है। लेवी परिकलन टीपीटी द्वारा अनुसरित पद्धति के अनुसार है, व्यय के संशोधित अनुमानों पर विचार करने को छोड़कर।

तदनुसार, मेन पूल कार्गो के लिए लेवी मेन पूल कार्गो के लिए लगभग ₹ 22.40 प्रति टन, कोयला जेट्टी II में कोयले के लिए ₹ 9.20 प्रति टन और नमक के लिए ₹ 41.00 प्रति टन परिगणित किया गया है।

- (ख). टीपीटीसीएचएलपी द्वारा प्रहस्तित नमक की मात्रा कम है। चूंकि यह कम मूल्य का कार्गो भी है, इसलिए टीपीटी ने प्रति सहायिकी के मौजूदा प्रवाह की अनुमति देते हुए मौजूदा लेवी को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। टीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

- (ग). टीएनईवी ने अनुरोध किया है कि कोयला जेट्टी II में प्रहस्तित कोयले पर टीपीटीसीएचएलपी लेवी का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तथापि, लागत स्थिति टीएनईवी के तर्कों का समर्थन नहीं करती है। जैसाकि टीपीटी द्वारा सही बताया गया है, कोयले को मेन पूल कार्गो से प्रति सहायिकी मिलती रही है और इसलिए उस सहायिकी को समाप्त करने के लिए उपयोक्ताओं के उस सैट से भाँग रही है। प्रशुल्क दिशा-निर्देश भी प्रति-सहायिकी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की अनुशंसा करते हैं।

लागत स्थिति के अनुसार, कोयला पर लेवी ₹ 9.20 प्रति टन परिगणित की गई है। इसलिए, कोयला के लिए लेवी ₹ 9.20 प्रति मीट्रिक टन है।

- (घ). मेन पूल कार्गो के संबंध में, लागत स्थिति पर आधारित लेवी ₹ 22.40 प्रति टन पर परिगणित की गई है। परंतु स्वीकार करते हुए कि टीपीटी ने कम मूल्य के नमक कार्गो को प्रति-सहायिकी का प्रस्ताव किया है, मेन पूल कार्गो के लिए लेवी ₹ 23 प्रति टन पर निर्धारित की गई है ताकि पत्तन द्वारा इस गतिविधि से वसूल किए जाने वाले अनुमानित व्यय को पूरा कर सके।

- (ङ). टीपीटी ने अंतरण रोड और बांदागार में सी एंड एफ प्रचालनों और जोन ख के लिए ₹ 10 प्रति मीट्रिक टन की मौजूदा लेवी को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। टीपीटी ने इस आधार पर कोई लागत व्यय नहीं भेजे थे कि इस गतिविधि से राजस्व नगण्य है। यह स्वीकार करते हुए कि प्रस्तावित लेवी पत्तन द्वारा पहले से वसूल की जा रही है और इसपर उपयोक्ताओं की ओर से भी आपत्ति नहीं है, इस श्रेणी को प्रदत्त सेवाओं के लिए ₹ 10 प्रति मीट्रिक टन की वसूली जारी रखने का टीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

- (च). टीपीटीसीएचएलपी से कामगारों की आपूर्ति के लिए मौजूदा लेवी एक बढ़ को छोड़कर जोकि समय दर मजदूरी के प्रतिशत पर आधारित है, अधिकांशतः प्रति टन दरों पर है। कंटेनर भरण और खाली करना के लिए लेवी समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत पर प्रस्तावित है। टीपीटी ने बताया है कि चूंकि टैली क्लर्कों की तैनाती इस प्रचालन के लिए नहीं की गई थी, इसलिए ऐसे कार्य के मामले में टनभार विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, लेवी समय दर के प्रतिशत पर आधारित है। कुछ उपयोक्ताओं ने लेवी को कम कर समय दर मजदूरी के 100 प्रतिशत पर करने का अनुरोध किया है। टीपीटी ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी पर व्यय का प्रतिशत उस 200 प्रतिशत से अधिक होगा और इसलिए उपयोक्ताओं का यह दावा कि मजदूरी के 200 प्रतिशत पर वर्तमान में वसूल की जा रही समय दर मजदूरी तथ्यों पर आधारित नहीं है।

टीपीटी द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण के आधार पर, कंटेनर भरण और खाली करना प्रचालनों के लिए समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत पर प्रस्तावित लेवी स्वीकार की गई है।

- (viii). (क). टीपीटी ने जीवनांककीय मूल्यांकन के आधार पर पेंशन निधि में कमी को पूरा करने के लिए गेन पूल कार्गो, कोयला जेट्टी II में प्रहस्तिर कोयला और नमक के लिए रु० 5 प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष लेवी शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

संशोधित विवरण में पेंशन देयता और उपदान देयता का जीवनांककीय मूल्यांकन 31 मार्च, 2007 को रु० 78.34 करोड़ अनुमानित किया गया है। 31 मार्च, 2007 की तत्संबंधी निधि में संचयित शेष दर विचार करने के पश्चात शेष पेंशन देयता रु० 23.88 करोड़ पर अनुमानित की गई है जोकि पांच वर्षों की अवधि में वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित है। संशोधित सफना के आधार पर, टीपीटी ने उक्त कार्गो मदों के लिए विशेष दर कम कर रु० 4.30 प्रति टन करने का प्रस्ताव किया है। पेंशन निधि देयता स्थिति का सार नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ों में)

1.	31 मार्च, 2007 को पेंशन और उपदान देयता का जीवनांककीय मूल्यांकन	78.34
2.	घटाएँ: 31 मार्च, 2007 को टीपीटी द्वारा प्रतिवेदित पेंशन निधि शेष	46.00
3.	31 मार्च, 2006 को शेष देयता (1-2)	32.34
4.	घटाएँ: क्षेत्रीय मविष्य निधि (तिरुनुवेली) से देय राशि	8.46
5.	वसूल की जाने वाला पेंशन निधि देयता शेष (3-4)	23.88
6.	पांच वर्षों में पेंशन निधि कमी	4.78
7.	प्रहस्तिर किए जाने के लिए संभावित औसत टनभार (लाख टन)	110
8.	पेंशन निधि लेवी	4.35

- (ख). संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खंड 2.5.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसी एक बार की देयता विशेष रूप से चिह्नित निधियों अथवा प्राक्धानों से इतर संचयित अधिशेषों/आरक्षित निधियों से पूरी की जा सकती है यदि इसे अभी भी पर्याप्ततः कवर नहीं किया गया है, तो पत्तन औचित्यपूर्ण कारणों से ऐसी देयताओं को पूरा करने के लिए सीमित अवधि हेतु विशेष दर प्रस्तावित कर सकता है। पत्तन द्वारा स्पष्ट की गई पेंशन निधि स्थिति में कमी के मद्देनजर, टीपीटी द्वारा प्रस्तावित विशेष दर पाँच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार की गई है।

- (ग). टीपीटी ने कुछ मदों के लिए विशेष दर लेवी का प्रस्ताव नहीं किया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पेंशन देयता विभिन्न गतिविधियों में तैनात टीपीटीसीएचएलपी योजना के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के सन्दर्भ में है। इसलिए, कुछ श्रेणियों के लिए विशेष लेवी से अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशेष दर केवल एक अधिकतम दर है और इसलिए पत्तन कम दर वसूल करने के अपनी अनुनयता का प्रयोग कर सकता है अथवा अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर इस लेवी से कुछ श्रेणियों को छूट दी जा सकती है।

- (घ). पेंशन निधि स्थिति और अब शुरू की गई विशेष दर की अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय समीक्षा की जाएगी। पत्तन को इस संबंध में एक पृथक लेखा व्यवस्थित और अगली समीक्षा के समय संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षित ब्योरे भेजने होंगे।

- (ix). संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों का खंड 4.7.2 अनुसंसा करता है कि पत्तन नौभरण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशुल्क से संबंधित उत्पादकता निर्धारित करे। यथा सहमत, पत्तन का सलाह दी जाती है कि अगले प्रशुल्क चक्र के दौरान लेवी की समीक्षा करते समय उत्पादकता से संबंधित स्लाइडिंग दरें प्रस्तावित करे।

- (x). संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करते हैं। चूंकि लेवी के निर्धारण के लिए सुविचारित लागत स्थिति दो वर्षों अर्थात् 2008-09 और 2009-10 के लिए है, इसलिए निर्धारित प्रशुल्क छिन्न पैपता अवधि के लिए होगा। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सुविचारित वित्तीय स्थिति कंपत 31 मार्च, 2010 तक है, इसलिए संशोधित दरमान की वैधता भी 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो जाएगी।

- (xi). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के पश्चात लागू की जाती है। चूंकि इस मामले को पत्तन के सामान्य संशोधन के समानान्तरतः अंतिम रूप दिया गया है, इसलिए यह उपयुक्त पाया गया है कि सामान्य संशोधन मामले में अनुमोदित टीपीटी के संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख से इस आदेश को कार्यान्वित किया जाए। टीपीटीसीएचएलपी से लेबर की तैनाती के लिए लेवी तदनुसार अध्याय-VI में टीपीटी के संशोधित दरमान में शामिल की गई है।

12. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण कार्गो ग्रहस्तन प्रचालनों के लिए तुतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो ग्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) से कार्गो ग्रहस्तन कामगारों की आपूर्ति के लिए टीपीटी के दरमान में निम्नलिखित अध्याय-VI का समावेशन अनुमोदित करता है:

अध्याय-VI

- 8.1. कार्गो ग्रहस्तन प्रचालनों के लिए तुतीकोरिन पत्तन न्यास कार्गो ग्रहस्तन लेबर पूल (टीपीटीसीएचएलपी) से लेबर की आपूर्ति के लिए लेवी

क्र. सं.	विवरण	प्रति मीट्रिक टन (मी०ट०)
1.	कोयला और नमक से इतर सभी कार्गो	रु० 23.00
2.	नमक	रु० 18.00
3.	जेट्टी II में कोयला	रु० 9.20
4.	कंटेनर भरण और खाली करना प्रचालनों के लिए	समय दर मजदूरी के 200 प्रतिशत की दर से
5.	अंतरण शौड और मांडागार आदि में सी एंड एफ प्रचालन लेवी	रु० 10/- प्रति मी०ट०
6.	जोन 'ख' के लिए	रु० 10.00 प्रति मी०ट०

8.2 पेंशन निधि लेवी

पेंशन निधि देयता में कमी को पूरा करने के लिए टीपीटी द्वारा रु० 4.30 प्रति मी०ट० की दर से पेंशन निधि लेवी वसूल की जाएगी। यह वसूली पाँच वर्षों की अवधि के लिए होगी, परंतु समीक्षा की जा सकेगी।"

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/08-असल]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th August, 2008

No. TAMP/17/2006-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixation of charges for supply of labour by Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool for cargo handling operations as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/17/2006-TPT

Tuticorin Port Trust

—Applicant

ORDER

(Passed on this 14th day of July, 2008)

This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixation of charges for supply of labour by Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool for cargo handling operations.

2. While revising the Scale of Rates of the TPT in September 2002, this Authority had held that if the members of the Labour Pool administered by the port trust are treated as port employees, the charges leviable for supply therefrom for cargo handling operations are to be fixed by this Authority. The TPT was, therefore, advised to examine the issue and file a suitable proposal to regulate cargo handling workers levy within six months time.

3.1. In this backdrop, the TPT has filed the instant proposal. The main points made by the TPT are as follows:

- (i). The Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) is a scheme formed vide Memorandum of Settlement dated 22 December 1999 under Section 12 (3) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the TPT and five unions representing the cargo-handling workers and staff of erstwhile Tuticorin Stevedores Association (Labour Pool). The scheme manages 1262 cargo handling workers and staff involved in relation to the cargo handling activities at Tuticorin port.
- (ii). As per the Memorandum of Settlement, the TPTCHLP supplies labourers to various stevedore agents for handling cargo.
- (iii). The following charges are collected for labour deployed from TPTCHLP for cargo handling operations in coal jetty II, general cargo berths viz. VOC 1 to 4, Additional berth I and II, 8th berth and shallow water berth:
- Time rate wages based on the actual pay and dearness allowance of the employees as per norms subject to changes in DA points every quarter.
 - Piece-rate wages based on the datum fixed.
 - Night waiting allowance as per the actual deployment of labour during the night shifts.
 - Cargo levy on per tonne basis is collected on the cargo handled to meet the expenditure on statutory commitments like medical facilities, provision of uniforms, safety materials, pension and gratuity payments, welfare expenditure towards employees and also administrative expenses for office administration and other overheads.
- (iv). The charges for supply of labourers for cargo handling activities are fixed by the TPT in consultation with the port users in Levy Finance Committee Meeting.
- (v). The current levy structure is as follows:

Sl. No.	Description	Per Metric Tonne (MT)
1.	All cargoes other than Coal and Salt	Rs.41/-
2.	Salt	Rs.18/-
3.	Coal at Jetty II	Rs.8.50/-
4.	C&F Operation at Transit Shed and Ware house etc levy	@ 200% of Time Rate wages
5.	For Zone 'B'	Rs.10/- Per M.T.

From 2004-05 onwards, rebate is offered on increased volume of cargo handled over the respective previous year.

- (vi). On study of the income and expenditure from this service at the current levy, it is found that the current level of levy is just sufficient to meet the requirement of TPTCHLP for the next two years 2006-07 and 2007-08.

The existing levy for coal at Rs. 8.50 PMT is very low. As regards main pool cargo, there is demand from users to reduce the levy. These issues were discussed with port users in a meeting held on 4 January 2008.

- (vii). The TPT has accordingly proposed the following changes in the existing levy structure:

- The existing levy for coal is proposed to be increased from Rs.8.50 per MT to Rs.15 per MT.

- The levy for main pool cargo (other than coal at coal jetty II and salt) is proposed to be reduced by Rs. 1 per MT i.e. from existing levy of Rs. 41 to Rs.40 per MT as requested by the users.
 - Levy for other cargo items is maintained at the existing level.
- (viii). The TPT has made the following submissions as regards the Pension fund liability of these workers:
- (a). By virtue of the Memorandum of Settlement, the TPTCHLP is to undertake the pension liabilities of the employees covered under the settlement at par with the TPT employees.
 - (b). Based on the representation of TPTCHLP and the sanction of Ministry of labour, the TPTCHLP has started maintaining the Pension Fund with effect from 1 January 2003.
 - (c). Pension fund shows a balance of Rs.32.39 crores as on 31 March 2005.
 - (d). As per the actuarial valuation done by Consulting actuary, the Pension fund liability as on 31 March 2004 is Rs.60.92 crores. Out of which Rs. 30.19 crores has been accumulated upto 31.03.2004 in the Pension fund. Balance amount of Rs.30.73 crores is still required to strengthen the Pension fund to match the actuarial valuation.
 - (e). In this back drop, it has proposed to recover Rs. 5 Per Metric Tonne (PMT) for the years 2006-07 and 2007-08 from the existing levy to meet the shortfall in pension fund liability.
- (ix). The TPT has estimated to collect R. 470.65 lakhs and Rs.486.24 lakhs for the years 2006-07 and 2007-08 respectively by introduction of proposed additional levy of Rs.5 PMT to meet shortfall in the pension liability. The modification proposed in the existing levy structure of TPTCHLP is estimated to generate additional earnings of Rs. 146.80 lakhs and Rs. 143.74 lakhs in the years 2006-07 and 2007-08 which is also proposed to be diverted to the Pension fund of these workers to quicken the accumulation of pension fund with respect to the actuarial valuation as on 31.3.2004.

3.2. To summarise, the existing levy for deployment of labour from TPTCHLP for cargo handling operations vis-à-vis the proposed levy is tabulated below:

Sl.No.	Description	Existing levy	Proposed Levy
1.	Levy for Main Pool cargoes (other than Coal at Coal Jetty II and Salt).	Rs.41/- per M.T.	Rs. 40/- per M.T.
2.	Levy for coal at Coal Jetty II	Rs.8.50 per M.T.	Rs.15/- per M.T.
3.	Rate for salt	Rs.18/- per M.T.	Rs.18/- per M.T.
4.	C&F Operation at Transit Shed and Warehouse etc., Levy	@ 200% of time rate wages	@ 200% of time rate wages
5.	Zone 'B'	Rs.10/- per M.T.	Rs.10/- per M.T.

In addition, it has proposed to recover Rs.5 per metric tonne for the years 2006-07 and 2007-08 to meet the Pension fund liability based on the actuarial valuation.

3.3. The TPT has furnished income and expenditure projections of Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) with proposed changes in levy structure for the years 2006-07 to 2007-08. It has also reported the actual position for the years 2003-04, 2004-05 and actual/estimates for 2005-06.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of TPT was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. The copy of the comments received from the users/ user organisations were forwarded to TPT as feedback information. The TPT has furnished its comments on the comments of users/user organisations.

5. On a preliminary scrutiny of the proposal, TPT was requested to furnish additional information/clarifications on a few points. A summary of queries raised by us and reply furnished by the TPT is tabulated below:

Sr. No.	Queries raised by us	Reply furnished by TPT
(i).	Indicate the existing manning scale for individual cargo items and the date when it was last revised.	It has furnished the existing manning scale for individual cargo items. The manning scale was last revised w.e.f. 01.01.1984.
(ii).	As per clause 4.7.3. of the revised tariff guidelines, ports need to revise the datum and rates of piece-rate scheme from time to time in terms of the National Wage Settlements. Further, clause 2.6.2. of the revised tariff guidelines require the port to regularly review the manning scale in view of technological changes. The action initiated by the port in this direction may be informed.	The National Tribunal constituted as per the Wage Revision Settlement between the Indian Port Association and the Federation of Port & Dock Workers' Unions is taking up the issue of revision of datum/ manning scale. Since the award of National Tribunal is binding as per the WRC Settlement, any adhoc decision on this issue is considered premature.
(iii).	Indicate the average days of employment of the cargo handling workers for the last two years.	Average days of the employment of workers for the last two years 2004-05 and 2005-06 are furnished. As per the data furnished, the average days of employment of labour are around 12 to 15 days in a month.
(iv).	Furnish productivity of the cargo handling workers for the last two years in terms of average output per hook per shift commodity-wise.	Commodity-wise average output per hook per gang for the last two years 2004-05 and 2005-06 are furnished.
(v).	Clause 4.7.2. of the tariff guidelines recommends the port to prescribe productivity linked tariff for providing stevedoring services. The TPT may, therefore, consider to prescribe sliding rates with increase in the productivity level. Such tariff arrangement is in vogue at the Mormugao Port Trust.	The sliding rates linked with productivity in Mormugao Port Trust will be analysed for appropriate decision if applicable for implementation in due course of time.
(vi).	Clarify, whether the existing levy was approved earlier by the Government of India prior to the last general revision Order of the TPT. If so, forward a copy of the gazette notification of the said Order.	The erstwhile administration of Tuticorin Stevedores' Association (Labour Pool) had constituted a levy Committee, consisting of the stevedores to decide the quantum of levy matching the commitment towards payment of salary/ wages and other benefits. On the formation of TPTCHLP from 01 January 2000, Management Committee headed by Dy. Chairman was constituted to manage the affairs of TPTCHLP. A levy Finance Committee was also constituted consisting of port officials and users. Commitment of the labour pool towards salaries and other benefits including Pension liability are presented to the members of Levy Finance Committee and after discussion, increase/ decrease in levy is arrived at based on a consensus. No Government approval was sought earlier and there is no Gazette notification of the levy charged by TPT at present.

(vi).	Explain the basis on which the existing per tonne levy is arrived at for deploying the TPTCHLP labour for cargo handling operations at the TPT. Also, furnish detailed computation for each cargo items in this regard.	<p>The erstwhile Administration of Tuticorin Stevedores' Association followed the practice of charging levy on per ton basis instead of percentage basis as adopted in some ports. The basis of arriving at the per tonne levy is explained below:</p> <p>(a). The assessment of the quantum of commitment towards all expenditure is made.</p> <p>(b). The cargo handled is divided into Main Pool cargo, cargo handled at Coal Jetty II and self.</p> <p>(c). Per ton rate is arrived at by apportionment of all expenditure (other than wages and piece rate recovered from the stevedores) on the basis of average hook shift for different cargo classification and dividing the apportioned expenditure by the projected tonnage. It is pertinent to point out that some cross subsidisation is inevitable for cargo like salt, Bulk cargo like copper concentrate, rock phosphate, industrial coal cross subsidises the low volume as well as low value cargo. Since a variety of cargo is handled at TPT and different methods are adopted by agents for handling the same cargo, calculation sheet for each cargo is not available.</p>
(vii).	Furnish an income and expenditure statement for TPTCHLP at the existing levy without reducing the amount proposed to be diverted to the pension fund.	The income and expenditure statement ignoring the contributions to Pension fund levy is furnished separately.
(ix).	Explain the basis of arriving at the fixed assets and the relevance of working capital for offering this service along with the detailed basis for this estimation.	The written down value after providing for depreciation as per provisions of the Income Tax Act is the base for arriving at the fixed assets of TPTCHLP. The working capital is arrived at based on the average financial commitment including monthly commitment towards Pension. This is estimated based on the salary/ benefits to be paid to employees of TPTCHLP as per WRC settlement.
(x).	Furnish detailed computation of the actuarial valuation of pension for the cargo handling workers. Also, furnish a copy of the report of the actuaries in this regard.	Copy of Actuarial Certificate of the Pension liability as on 31 March 2004 is furnished. It has subsequently furnished detailed computation of pension fund levy.
(xi).	Furnish a copy of the Audited Accounts of the TPTCHLP for the last two years. Also, furnish accruals for the year 2005-06 upto 31 January 2006.	It has forwarded copy each of Audited Accounts of TPTCHLP for the last three years 2002-03, 2003-04 and 2004-05.
(xii).	Justify the proposed increase in the existing levy for coal handling only for the purpose of recovering the pension fund liability.	The observation that the increased Coal Levy only is used for the purpose of Pension Fund is not correct. It is stated that all cargo items contribute to the Pension Fund Liability. Pension Fund liability is the commitment of labour pool and it has to be accumulated as per the actuarial valuation. All along the coal has been subsidised at the cost of other cargo items of main pool other than salt. The statement of calculation showing the per tonne cost arrived at based on gang shift output at the projected expenditure level is enclosed. Based on this calculation, the levy for coal is proposed to be increased to Rs.15/- per PMT as against per tonne cost of Rs.17.54 PMT.

(xiii).	A separate per tonne levy to meet the pension fund liability must be discontinued when the pension contribution based on the actuarial valuation is recovered. This requires regular review of a separately maintained account head for this purpose. The port may suggest a suitable monitoring mechanism in this regard.	It has confirmed that Rs.5/- per MT, identified as Pension Fund levy is transferred to meet the Pension fund liability and it will be discontinued as and when the liability as per actuarial valuation is met in full. It has reiterated that the proposed Pension Fund levy is one time arrangement and shall continue to be maintained separately. The very fact of keeping a separate head of accounts itself serves as a monitoring mechanism.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. A joint hearing in this case was held on 13 July 2007 at the Tuticorin Port Trust premises. At the joint hearing, the TPT and the users/user associations made their submissions. The Tuticorin Customs House Agents Association (TCHAA) filed written submissions reiterating the points made by it earlier. In addition to that, it has appreciated the TPT for having reduced the levy on main pool cargo from Rs.41/- to Rs. 31 Per Metric Tonne (PMT) and has requested for further reduction to Rs. 25/- PMT if not less.

7. As agreed in the joint hearing, the TPT was advised to file a revised proposal along with revised cost statements giving actual position for the past 3 years and estimates till 2009-10 so that the validity can be made co-terminus with the general revision case.

8.1. The Tuticorin Port has accordingly filed a revised proposal in September 2007. It has also submitted the revised statements updating actuals upto 2006-07 and has revised the estimates for the years 2007-08 to 2009-10. A summary of the revised statement filed by the TPT for the years 2007-08 to 2009-10 alongwith actuals for 2004-05 to 2006-07 is tabulated below.

(Rs. in lakhs)								
Sl. No.	Description	Actuals			Estimates			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Average for the years 2007-08 to 2009-10
1.	Operating expenditure	2662.89	2689.27	2770.00	2919.58	3077.24	3243.41	3080.07
2.	F&M expenditure	1003.66	755.85	729.34	768.25	809.74	853.46	810.48
3.	Salary/wage revision 25%				448.64	669.97	673.31	596.64
4.	Return on Capital employed	15.22	16.48	16.96	19.22	19.22	19.22	19.22
5.	Total expenditure	3681.77	3461.60	3516.30	4153.69	4576.17	4789.40	4506.41
6.	Less: wages Recovered	1252.35	1387.10	1539.33	1630.06	1692.03	1753.08	1691.72
7.	Balance expenditure to be recovered	2429.42	2074.50	1976.97	2523.83	2884.14	3036.32	2814.69

8.2. The computation furnished by TPT for arriving at the revised proposed levy based on average hook shifts is given below:

Sl. No.	Description	Average Hooks shifts	Expenditure to be recovered (Rs. in lakhs)	Average tonnage handled (in lakh tones)	Rate per Tonne (in Rs.)	Pension Fund levy (Rs. per tonne)
1.	Main Pool- others	17037	2363.09	77.00	31	4.30
2.	T/Coal at Coal Jetty II	2855	395.99	32.00	12	4.30
3.	Salt	401	55.82	1.00	56	4.30
	Total	20,293	2814.70	110.00		

8.3. Accordingly, the revised levy structure proposed by TPT vis-a-vis its initial proposal is as follows:

Sl. No.	Description	Levy proposed in initial proposal	Levy proposed in revised proposal
1.	Levy for Main Pool cargoes (other than Coal at Coal Jetty II and Salt).	Rs. 40/- per M.T.	Rs. 31/- per M.T.
2.	Levy for coal at Coal Jetty II	Rs.15/- per M.T.	Rs.12/- per M.T.
3.	Rate for salt	Rs.18/- per M.T.	Rs.56/- per M.T.
4.	C&F Operation at Transit Shed and Warehouse etc., Levy	@ 200% of time rate wages	200% of time rate wages

5.	For Zone 'B'	Rs.10/- per M.T.	Rs.10/- per M.T.
Pension fund levy of Rs. 4.30 per MT for items mentioned at Sl. No. 1, 2 and 3 above is proposed for the next five years to meet the shortfall in the Pension fund liability based on the actuarial valuation as against Rs. 5/- per MT proposed in the initial proposal.			

8.4. Detailed computation of Pension fund levy furnished by TPT is given below:

	Rs. in lakhs
1. Actuarial valuation as of 31.03.2007	7800.00
2. Pension fund balance for the year ended 2006-07	4600.00
3. Add: Balance Amount expected to be received from Regional Provident Fund Commissioner	846.34
4. Total fund available in the Pension Fund as on 31 March 2007	5446.34
5. Short fall in the Pension fund to meet the actuarial valuation (1-4)	2353.66
6. Short fall in pension fund to be recovered over 5 years.	470.73
7. Pension fund levy (6 / average expected tonnage i.e. 110 lakh tonnes per annum)	4.30

It has accordingly proposed to reduce the pension fund levy to Rs. 4.30 PMT in respect of main pool cargo, coal at Coal Jetty II and salt as against Rs.5 PMT proposed in its initial proposal.

9. In view of some gaps observed in the revised proposal, the TPT was requested to furnish additional information/ clarifications. A summary of queries raised and reply furnished by TPT is tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Reply received from TPT
(i).	A copy of Audited Accounts of Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) for the years 2005-06 and 2006-07.	It has furnished a copy of Audited Accounts of Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) for the years 2005-06 and 2006-07.
(ii).	Furnish the basis of the traffic estimated to be handled by the labour pool deployed by TPTCHLP, income and expenditure estimations for the years 2007-08 to 2009-10.	The traffic estimated for the year 2007-08 is worked out proportionately with reference to traffic handled in July 2007. For the years 2008-2009 and 2009-2010, the traffic increase is considered at 5% increase per annum. Expenditure are projected considering 5.4% escalation per annum with reference to previous year actuals/estimates.
(iii).	(a). Explain the reasons for including both contribution to pension fund as well as pension payments / commutation of pension in the FME for the years 2004-05 and 2005-06. It may be noted that pension payments to the extent not drawn from the pension fund and contribution made to the pension fund for the relevant years towards pension liability of existing employees will be allowed in tariff fixation process	Regarding contribution to pension fund and pension payments met from general account, the contribution to pension fund represents the liability for each of the years 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010 calculated at 15% on basic pay plus DA and the pension payments are met from revenue expenditure. Hence this is in order. The pension payments/commutation of pension represent expenditure incurred for the existing pensioners, the contribution to pension fund represent the annual liability towards the pension fund to be met during each of the years.
	(b). Confirm that one-time expenses such as arrears in wages, VRS compensation are excluded from the FME as per clause 2.5.2. of the revised tariff guidelines.	It is confirmed that one time expenses such as arrears in wages VRS compensations are not included in the FME expenditure.
(iv).	Furnish detailed computation of capital employed and ROCE for the years 2005-06 to 2009-10 with reference to the figures considered in its revised proposal. While computing capital employed, the working capital may be estimated in line with the norms prescribed in the revised tariff guidelines.	It has furnished detailed computation of capital employed consisting of fixed assets and working capital.
(v).	(a). Furnish detailed computation of the actuarial valuation of pension fund for cargo handling workers estimated at Rs. 78 crores as on 30 June 2007 in the revised proposal. A copy of the report of actuaries in this regard may also be furnished.	It has indicated that the actuarial valuation of pension fund will be Rs. 78.34 crores as on 31 March 2007.

	<p>(b). The Pension balance of Rs.4600 lakhs and Rs.846.34 lakhs (from RPFC) considered in the computation of pension levy is not found in the Annual Accounts of TPTCHLP for the year 2006-07.</p> <p>Substantiate this estimate with some documentary support from where it is obtained.</p>	<p>Pension fund balance of Rs.4600 lakhs is based on the following accumulations:</p> <table> <tr> <th colspan="3">(Rs. in lakhs)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Employees contribution received from Regional Provident Fund Commissioner (RPFC)</td><td>1,893.83</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pension Fund Levy for the period from 2004-05 to 2006-07</td><td>1,969.95</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Interest earned on the investment from Government Securities, State Development Loans and Fixed Deposits</td><td>736.22</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>4,600.00</td></tr> </table> <p>Regarding Rs.846.34 lakhs (due from RPFC), the amount represents the withdrawal benefits to be received from RPFC, Tirunelveli of Rs.575.03 lakhs together interest upto 31.12.2002, after which, TPTCHLP managed. This is in lieu of the Employer's contribution made by the erstwhile Tuticorin Stevedores Association upto 31.12.1999.</p>	(Rs. in lakhs)			1.	Employees contribution received from Regional Provident Fund Commissioner (RPFC)	1,893.83	2.	Pension Fund Levy for the period from 2004-05 to 2006-07	1,969.95	3.	Interest earned on the investment from Government Securities, State Development Loans and Fixed Deposits	736.22	Total		4,600.00
(Rs. in lakhs)																	
1.	Employees contribution received from Regional Provident Fund Commissioner (RPFC)	1,893.83															
2.	Pension Fund Levy for the period from 2004-05 to 2006-07	1,969.95															
3.	Interest earned on the investment from Government Securities, State Development Loans and Fixed Deposits	736.22															
Total		4,600.00															
(vi).	<p>The TPT in its initial proposal which was circulated to users as well as at the joint hearing held on 13 July 2007 had proposed to continue with the existing levy of Rs. 18/- per M.T. in respect of salt. The reasons and the basis for proposing to increase levy on salt from Rs. 18/- per M.T. to Rs. 56/- per M.T. in the revised proposal needs to be justified since such revision did not form part of its initial proposal that was circulated to the users.</p>	<p>The proposed rate of Rs.18/- per ton is to exhibit the prevailing rate of salt. The rate of Rs.56/- per metric ton is to indicate the actual rate of levy to be recovered from salt with reference to its hooks shifts tonnage. However, Rs.18/- per metric ton will be the actual rate of levy for salt.</p>															
(vii).	<p>(a). The TPT in its letter No. TPTCHLP/SOR/REV/2006/D- dated 21 June 2006 had clarified that the proposed rate of 200% of time rate wages for C&F operation at Transit Shed and Warehouse etc., in the initial proposal was incorrect. The TPT had confirmed that as per the existing levy in force, the levy for cargo involving container stuffing / destuffing operations is 200% of time rate of wages and for C&F operations at Transit Sheds, Ware House and for handling cargo at Zone B the levy is Rs. 10/- per M.T. The revised proposal filed by TPT, however, does not reflect the said modification</p>	<p>The 200% of time rate of wages is for container stuffing and destuffing operations only. For others like C&F operations, Transit Shed, Warehouse & Zone B, it is confirmed that the rate of Rs.10/- metric ton holds good. This may be suitably incorporated in the Order of the Authority.</p>															
	<p>(b). Furnish the working for arriving at the levy for C&F operations at Transit Shed and Warehouse at 10 per metric tonne and 200% of time rate wages for cargo involving stuffing and de-stuffing operations and C&F operations at Transit Shed and Warehouse.</p>	<p>The said operations of C&F operations are very meager. The calculations for 200% of time rate of wages has already been furnished. Regarding Rs.10/-metric ton for C&F operation in Transit Shed & Zone B the same is a traditional rate and due to meager operation, the amount collected in this regard is almost nil for the past two years.</p>															
(viii).	<p>Though the levy is proposed to be collected from other items viz. cargo involving stuffing and de-stuffing operations and C&F operations at Transit Shed and Warehouse, the expenditure relating to TPTCHLP is not found to be apportioned to these cargo items/ activities. The income estimation also do not reflect the income from these items. In the light of the above observation, the TPT may consider to modify the statement to reflect this position.</p>	<p>From the calculation furnished by TPT, it is found that the un-bidged expenditure of TPTCHLP is proposed to be recovered from main pool cargo, coal handled at coal jetty II and the salt. The other operations of C&F at Transit Shed, Warehouse are very meager and the collection is only around Rs.2.00 lakhs per annum.</p>															

10. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

11. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). Consequent upon an industrial settlement reached in December 1999, the workers and staff of the Tuticorin Stevedores Association (Labour Pool) were brought under a separate scheme known as Tuticorin Port Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP). The scheme was made effective from January 2000.

The levy for supply of cargo handling workers from the TPTCHLP is reportedly being fixed by the TPT in consultation with the port users in the Levy Finance Committee Meeting.

The TPTCHLP is administered by the TPT though under a different name. The rates for supply of the cargo handling workers from the pool is required to be approved by this Authority as this is in connection with service listed under Section 48. This position was pointed out to the TPT at the time of the last general revision of its Scale of Rates of the port in the year 2002. It took nearly four years for TPT to act based on the advice rendered.

At this juncture, this Authority may not like to go into the procedural propriety of the charges levied based on the rate fixed by the Committee without an explicit approval accorded thereto under the provisions of the Major Port Trust Act and none of the users have also agitated this issue.

- (ii). The TPT has indicated that the existing manning scales for individual commodities were last revised in 1984. The Memorandum of Settlement of 1999 provides for revision in the manning scales, datum and piece rate incentives. Some of the users have stated that the manning pattern, datum level, needs to be examined and rationalised by the port and has also requested this Authority to address this issue before revising the levy.

The tariff guidelines require the port to regularly review the manning scale in view of technological changes. The port is also required to revise the datum and rates of piece-rate scheme from time to time in terms of the National Wage Settlements.

The TPT has, however, maintained that the National Tribunal constituted as per the Wage Revision Settlement between the Indian Port Association and the Federation of Port & Dock Workers' Unions have taken up the issue of revision of datum/ manning scale. Since the award of National Tribunal is binding as per the Wage Revision Committee Settlement, the TPT feels that any adhoc decision on this issue will be considered premature.

It is admitted that wage cost depending on the manning scales and datum adopted will have a definite tariff implication. It has to be recognized that fixing of manning scales and datum is a port management function. Since the revision in the datum / manning pattern of major ports is reportedly under consideration by the National Tribunal, the levy is fixed based on the existing manning scale/ datum reported in the proposal by the TPT.

Notwithstanding this position in this tariff case, the TPT is advised to initiate action to revise the datum for different commodities in terms of the provisions contained in the National Level Wage Agreement.

- (iii). In response to the original proposal of TPT, many of the users had demanded further reduction in the levy in respect of main pool cargo. The TNEB found the proposed rate for coal to be exorbitant and had requested the port to reduce the rate.

The TPT acceded to the demand of the users and agreed at the joint hearing, to reduce the levy for main pool cargo from Rs. 40 proposed in its initial proposal to Rs. 35 PMT and Rs. 10 PMT for handling coal. The revised proposal filed by the TPT subsequently relying upon the cost position, however, contained slight variations from the position agreed at the joint hearing.

- (iv). The cost statement of the TPTCHLP filed by the TPT is examined to assess the reasonableness of the rates proposed.

The TPT has furnished the actual income and expenditure of TPTCHLP activity for the years 2004-05 to 2006-07 and estimates for the next three years 2007-08 to 2009-10. The year 2007-08 is already drawn to a close. Hence, the estimates for the years 2008-09 and 2009-10 are only relevant in this tariff fixation exercise. Consequently, the validity of the levy revised to be approved now will be for a truncated validity period of around one and half year from the date of its implementation.

The cargo volume expected to be handled by the main pool of TPTCHLP is estimated to increase by 5% per annum over the actuals / estimates of the respective previous year. The volume of coal traffic to be handled by TPTCHLP is estimated almost at the level of 2006-07 for three years under consideration.

The traffic increase estimated by the TPT in the general revision proposal may not be fully relevant for this particular case since all the cargo will not be availing the services of TPTCHLP. The traffic estimated by the TPT in this case is relied upon for fixation of levy.

However, if any undue advantage is found to have accrued to the TPT due to wrong estimation, adjustment will be made in the tariff at the time of next review of tariff in line with the tariff guidelines.

- (v). (a). The operating expense for the year 2007-08 is estimated to increase by 5.4% over the actuals reported in the year 2006-07. The expenses for the subsequent two years 2008-09 and 2009-10 are estimated applying the same escalation factor of 5.4%.

The tariff guidelines stipulate that the expenditure is to be projected in line with traffic adjusted for price fluctuation with reference to the current movement of Wholesale Price Index (WPI) for all commodities announced by the Government of India. The WPI announced by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry for the year 2007-08 is 4.6%. Accordingly, the WPI to be considered by the Authority for the tariff revision exercise in the year 2008-09 is 4.6 %. The estimation of expense for the years 2008-09 and 2009-10 is therefore modified restricting annual escalation at 4.6%.

- (b). The estimation of Finance and Miscellaneous Expense include pension / gratuity payments as well as provision for contribution to pension Fund and Gratuity Fund for the years under consideration. The port has clarified that the pension payments for TPTCHLP workers is made from the revenue account and the provision relates to the annual contribution made to the pension fund to the extent of 15% of the basic and DA. The pension payment of the existing pensioners has to be met from the Pension Fund. Hence, for fixation of levy only the contribution proposed to be made to the Pension fund and gratuity fund is considered as estimated by the TPT.

- (c). The total salaries and wages for the year 2007-08 is estimated at Rs.1786.57 lakhs. The TPT has made a provision for wage revision at 25% of the total wage cost for the year 2007-08. Recognising that this item is only a provision, it is found sufficient to consider the impact of wage revision at 15% of the wages cost estimated for the year 2007-08 in line with the decision taken for other major ports like the Visakhapatnam Port Trust, New Mangalore Port Trust as well as the general revision proposal of the TPT which is being processed separately.

The TPT has estimated around 50% increase in the provision for wage revision for each of the years 2008-09 and 2009-10. The reason for such a steep increase is not explained. The port has not estimated any increase in the strength of labour force during these two years. In fact the port has emphasised the efforts done during the recent past to reduce the labour force. There is, therefore, no justification for considering the estimated wage cost beyond the permissible annual escalation level which is considered at 4.6 % per annum. The provision for wage revision for the years 2008-09 and 2009-10 are modified suitably to that extent.

- (vi). The TPT has computed the working capital for the year 2004-05 and applied 10% annual increase for the subsequent years for estimation of working capital for the years 2005-06 to 2009-10. The computation of working capital is not as per the norms prescribed in the tariff guidelines. The working capital for the year 2006-07 based on the norms prescribed in the tariff guidelines works out to a negative figure. Hence the estimate of working capital for the years 2007-08 to 2009-10 is taken as nil.

The TPT has confirmed that the depreciation is computed as per the Companies Act in line with the tariff guidelines which is accepted. The value of net fixed assets reported in the Annual Accounts for the year 2006-07 and that included in the computation of capital employed differ mainly because of different method of computation of the depreciation.

The value of net fixed assets furnished by the TPT in the cost statement for the years 2006-07 and 2007-08 are relied upon in this analysis. The TPT has not furnished the computation of capital employed for the year 2008-09 and 2009-10. In the absence of this information and also recognising that the port has not proposed any addition to the gross block of assets during these years, the net fixed assets for the subsequent years 2008-09 and 2009-10 is derived by reducing the depreciation amount from the estimates of the net block of previous year.

- (vii). (a). The average total expenditure of the TPTCHLP plus the return on capital employed after carrying out the aforesaid modifications works out to be Rs. 3822.59 lakhs for the years 2008-09 and 2009-10. Out of this, on an average Rs. 1722.56 lakhs of wages is estimated to be recovered by the TPT for the relevant years. The balance expenditure of 2100.13 lakhs is to be recovered by way of the proposed levy.

The estimated expenditure is allocated over the cargo items based on the average hook shifts and the levy per tonne of cargo is computed for the volume of cargo expected to be handled. The computation of levy is in line with the method followed by the TPT except for considering it on the modified estimates of expenditure.

Accordingly, the levy for main pool cargo works out to around Rs. 22.40 per tonne for main pool cargo, Rs. 9.20 per tonne for coal at coal Jetty- II and Rs. 41.00 per tonne for salt.

- (b). The volume of salt handled by the TPTCHLP is low. Also since it is a low value cargo, the TPT proposes to continue with the existing levy allowing existing flow of cross subsidy to continue. The proposal of the TPT is accepted.
- (c). The TNEB has requested that there should not be any revision of TPTCHLP levy on the Coal handled at Coal Jetty II. However, the cost position does not support the argument of the TNEB. As rightly stated by the TPT, coal had been enjoying cross subsidy from the main pool cargo and hence there has been demand from that set of users to eliminate the subsidy. Even the tariff guidelines recommend eliminating cross subsidy in a phased manner.

As per the cost position the levy on coal works out to Rs.9.20 per tonne. Hence, the levy for coal is fixed at Rs. 9.20 per metric tonne.

- (d). As regards the main pool cargo, the levy based on the cost position works out to Rs. 22.40 per tonne. But recognising that the TPT proposes to cross-subsidise the low value cargo salt, the levy for main pool cargo is fixed at Rs. 23 per tonne so that the port can meet the estimated expenditure to be recovered from this activity.
- (e). The TPT has proposed to continue with the existing levy of Rs 10 per metric tonne for C&F Operations in transit shed and ware house and for Zone B. The TPT has not furnished any cost details on the ground that the revenue from this activity is negligible. Recognising that the proposed levy is already being collected by the port and there has been no pointed objection from the users, the proposal of the TPT to continue to collect Rs. 10 per metric tonne for services rendered to this category is accepted.

- (f). The existing levy for supply of workers from the TPTCHLP is mostly on per tonne rates except for one item which is based on percentage of time rate wages. The levy for container stuffing and destuffing is proposed at 200% of the time rate wages. The TPT has reported that since posting of tally clerks is not made for this operation, tonnage particulars is not available in respect of such work. Hence, the levy is based on percentage of time rate.

Some of the users have requested to reduce the levy to 100% of the time rate wages. The TPT has clarified that the percentage of expenditure on wages works out to be more than 200% and hence the contention of the users that the time rate wages presently collected at 200% of wages is not based on the facts.

Based on the clarification furnished by the TPT, the proposed levy at 200% of time rate wages for container stuffing and destuffing operations is accepted.

- (viii) (a). The TPT proposed to introduce a special levy @ Rs. 5 per metric tonne for main pool cargo, coal handled at coal jetty II and salt to meet the short fall in the pension fund based on the actuarial valuation.

The actuarial valuation of pension liability and gratuity liability is estimated at Rs.78.34 crores as on 31 March 2007 in the revised statement. After considering the accumulated balance in the respective fund as on 31 March 2007, the balance pension liability is estimated at Rs.23.88 crores which is proposed to be recovered over five years period. Based on the revised calculation, the TPT has proposed to reduce the special levy to Rs. 4.30 per tonne for the said cargo items. A summary of the Pension fund liability position is given below:

(Rs. in crores)		
1.	Actuarial valuation of Pension and Gratuity liability as on 31 March 2007.	78.34
2.	Less: Pension Fund Balance reported by the TPT as on 31 March 2007.	46.00
3.	Balance Liability as on 31 March 2006. (1-2)	32.34
4.	Less: Amount due from Regional Provident Fund (Trinulveli)	8.46
5.	Balance Pension fund liability to be recovered. (3-4)	23.88
6.	Pension fund short fall spread over five years	4.78
7.	Average tonnage expected to be handled (lakh tonnes)	110
8.	Pension fund levy	4.35

- (b). Clause 2.5.2. of the revised tariff guidelines stipulates that such one time liability are to be met from the accumulated surpluses / reserves other than specifically earmarked funds or provisions and if it is still not adequately covered, then the port may for justifiable reasons, propose a special rate for a limited period to meet such liabilities. In view of the short fall in the pension fund position explained by the port, the special rate proposed by the TPT is allowed for five years period.
- (c). The TPT has not proposed to levy the special rate for certain items. It may be relevant to mention that the pension liability is with reference to all the employees and the pensioners of the TPTCHLP Scheme who are deployed in the various activities. Hence there is no justification to exclude the special levy for certain categories. The special rate prescribed by this Authority is only a ceiling rate and hence the port may exercise its flexibility to charge a lower rate or even exempt certain categories from this levy based on their commercial judgment.
- (d). The pension fund position and the special rate introduced now will be reviewed at the time of next tariff review. The port should maintain a separate account in this regard and furnish the audited details for scrutiny at the time of the next review.
- (ix). Clause 4.7.2. of the revised tariff guidelines recommends the port to prescribe productivity linked tariff for providing stevedoring services. As agreed, the port is advised to propose sliding rates linked with productivity while reviewing the levy during the next tariff cycle.

- (x). The revised tariff guidelines stipulate a tariff validity cycle of 3 years. Since the cost position considered for fixation of levy is for two years i.e. 2008-09 and 2009-10, the tariff prescribed will be for a truncated validity period. The financial position considered for the purpose of this analysis is only till 31 March 2010, hence the validity of the revised Scale of Rates will also expire on 31 March 2010.
- (xi). The rates approved by this Authority are to be implemented after 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Since this case has been finalised simultaneously with the general revision of the port, it is found appropriate to implement the Order from the date of implementation of the revised Scale of Rates of the TPT approved in the general revision case. The levy for deployment of labour from the TPTCHLP is accordingly incorporated in the revised Scale of Rates of the TPT in Chapter - V I.
12. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves insertion of the following Chapter -VI in the Scale of Rates of the TPT for supply of cargo handling workers from the Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) for cargo handling operations:

"Chapter V I

6.1 Levy for supply of labour from Tuticorin Port Trust Cargo Handling Labour Pool (TPTCHLP) for cargo handling operations

Sl. No.	Description	Per Metric Tonne (MT)
1.	All cargoes other than Coal and Salt	Rs.23.00
2.	Salt	Rs.18.00
3.	Coal at Jetty II	Rs.9.20
4.	For container stuffing and destuffing operations	@ 200% of Time Rate wages
5.	C&F Operation at Transit Shed and Ware house etc levy	Rs.10/- Per M.T.
6.	For Zone 'B'	Rs.10.00 Per M.T.

6.2 Pension fund levy

Pension fund levy @ Rs. 4.30 per M.T. to be collected by the TPT to meet the shortfall in the Pension fund liability. The levy will be for a period of five years, subject to review."

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/08-Exdy.]

3251 GT/08-7